Commission's recommendations, if there are proposals, we can consider. At the moment, the NEP says that there is no need to open new Central Universities; instead, the existing universities should be strengthened. I can assure the hon. Member that if the UGC recommends upgradation or assistance to any University in Orissa, the Ministry will be too happy to help it.

पर्यावरण रक्षा जागरूकता

*445. **श्री हरीश रावत:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका मंत्रालय पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील राज्यों में पर्यावरण रक्षा जागरूकता को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कार्य योजना बना रहा है;

(ख) क्या ऐसे राज्यों में विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में वन और पर्यावरण संवर्धन को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू): (क) सरकार जनता के बीच पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से वर्ष 1986 से प्रत्येक वर्ष, राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान (एन ई ए सी) नामक राष्ट्रव्यापी अभियान पहले से ही चला रही है।

(ख) और (ग) सभी राज्यों के स्कूली पाठ्यक्रमों/पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण से संबंधित विषय पहले ही सम्मिलित कर दिए गए है। परन्तु इस प्रकार शामिल किए गए विषयों को सुस्पष्ट करने के उद्देश्य से सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से 8 राज्यों में प्रायोगिक परियोजना शुरू की है।

Environment protection awareness

†*445. SHRI HARISH RAWAT: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether the Ministry of Environment and Forests are preparing some action plan to encourage environment protection awareness in the States, that are sensitive from environment point of view;

(b) whether there is a proposal to include forest and environment promotion in the school courses in such States; and

†Original notice of the question was received in Hindi.

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI T.R. BAALU): (a) The Government has already been conducting a nation-wide campaign known as National Environment Awareness Campaign (NEAC) every year since 1986 for creating environmental awareness among public.

(b) and (c) The environmental concepts have already been infused in the school courses/textbooks in all the States. However, with a view to strengthen the infusion, the Government has taken up a pilot project in 8 States with the assistance of the World Bank.

श्री हरीश रावत: सर, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि 8 राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों में पर्यावरण संबंधी जानकारियों की शिक्षा देने की योजना को राज्यों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, मगर उन्होंने ऐसे राज्यों के नाम नहीं बताए हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे राज्य कौन से हैं जहां पाठ्यक्रम में पर्यावरण संबंधी विषयों को पढ़ाने के लिए विश्व बैंक की सहायता दी जा रही है? क्या पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील राज्य जो मध्य हिमालय के हैं जैसे हिमाचल है, उत्तरांचल है, जम्मू-कश्मीर है, वे भी इसमें सम्मिलित हैं या नहीं?

श्री सभापति: ठीक है, आपने प्रश्न कर लिया है।

SHRI T.R. BAALU: Sir, the names of the States where this pilot project on environment education has taken up are, Andhra Pradesh, Assam, Goa, Jammu and Kashmir, Maharashtra, Orissa, Punjab and also Uttaranchal. We have made an allocation of Rs. 8.83 crores. Each of these States has about one hundred such schools and almost 800 schools have started this course.

श्री हरीश रावत: सभापति जी, मंत्री जी ने जो धनराशि बताई है, वह बहुत कम है और विश्व मंच पर हम बराबर इस बात को कहते रहते हैं कि विकसित देशों को, विकासशील राज्यों में पर्यावरण संबंधी जो संवेदना है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बराबर मदद देनी चाहिए मगर अपने देश के अंदर हम ऐसे राज्यों को जो पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील हैं, मगर जहां फॉरेस्ट कवर बहुत ज्यादा है जैसे उत्तरांचल है, 60 परसेंट से ज्यादा उस राज्य में फॉरेस्ट कवर है।

श्री सभापति: सीधा क्वेश्चन कीजिए।

SHRI HARISH RAWAT: I am coming to the question. 60 परसेंट से ज्यादा फॉरेस्ट कवर है तो ऐसे राज्यों को ताकि वे अपने फॉरेस्ट कवर को बनाए रख सकें और इकानॉमिक ऐक्टिविटीज़ की वजह से वहां के फॉरेस्ट कवर पर जो प्रेशर है, उसको हटाया जा सके, उनकी विशेष

सहायता करने की योजना पर आप कोई विचार कर रहे हैं? क्या ऐसे कोई दृष्टिकोण है?

SHRI T.R. BAALU: Sir, the programmes are not suffering for want of funds. This particular State, namely, Uttaranchal, will be sending us a proposal and we will definitely be assisting them.

SHRIMATI S.G. INDIRA: Sir, I would like to know from the hon. Minister whether this programme is likely to be extended to other parts of the country, particularly Tamil Nadu.

SHRI T.R. BAALU: Sir, Tamil Nadu is one of the developed States. I do not think it is necessary as such to have this programme there.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: This campaign is good. But the Ministry needs more teeth. Therefore, will the hon. Minister like to think of bringing in some law so that this programme is implemented effectively, and the culprits are dealt with severely? I would also like to know whether the Ministry is going to take some action against those States which are not taking this issue of environment seriously, because this is going to be a serious problem.

SHRI T.R. BAALU: I do agree that NEAC does not have enough teeth at present. But my intention is not to bite any State. The States have to behave properly. That is my intention.

राजस्थान और उड़ीसा में केन्द्रीय विश्वविद्यालय

*446. श्री जनेश्वर मिश्र: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार कितने केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं;

(ख) किस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि राजस्थान और उड़ीसा जैसे राज्यों में कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।